RNI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 143
दि. 22.09.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं

शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ सोमवार से हो रहा है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर योगी आदित्यनाथ शक्ति स्वरूप मां जगदंबा की विशेष पूजा

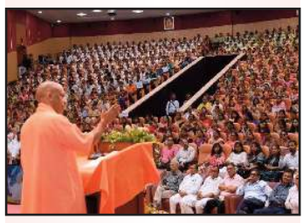

अर्चना करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी नवरात्र की अष्टमी तिथि में विधि विधान से महानिशा पूजन और हवन कर लोक मंगल की प्रार्थना करेंगे।

पीएम मोदी का बड़ा ऐलान – 22 सितंबर से शुरू होगा ' जीएसटी बचत उत्सव', संबोधन की महत्वपूर्ण बातें

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम देश को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर की सुबह से ही देश में 'GST बचत उत्सव' शुरू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक बदलाव का सीधा असर हर वर्ग के लोगों की जेब पर पड़ेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरूआत नवरात्रि की बधाई देकर की और इसे देश की आर्थिक मजबूती की दिशा में अहम कदम बताया।

'बचत उत्सव' से हर परिवार को राहत

पीएम मोदी ने कहा कि इस बचत उत्सव का लाभ गरीब, मध्यमवर्गीय, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं और व्यापारी सभी को मिलेगा। त्योहारों के इस मौसम में लोग अपनी पसंद का सामान सस्ती कीमतों पर खरीद पाएंगे। मोदी ने कहा, "हर घर में खुशहाली होगी, हर परिवार का मुंह मीठा होगा। यह सुधार भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई गति देगा।"

निवेश और कारोबार पर सकारात्मक असर

प्रधानमंत्री ने बताया कि नए GST ढांचे से कारोबार करना आसान होगा। देशी-विदेशी निवेशकों को भारत और ज्यादा आकर्षक बाजार लगेगा। उन्होंने जोर दिया कि इस सुधार से हर राज्य को बराबरी का मौका मिलेगा और विकास की रफ्तार तेज होगी।

◆ 1. पीएम मोदी ने कहा, "जो देश के लोगों की जरुरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं। वो हमें देश में ही बनाना चाहिए।"

◆ 2. पीएम मोदी ने कहा, "हम वो सामान खरीदें जो MADE IN INDIA हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे-बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है।"

◆ 3.पीएम मोदी ने कहा, "जो देश के लोगों की जरुरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली... वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी।"

◆ 4. पीएम मोदी ने कहा, "GST कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। इस जीएसटी रिफॉर्म में 'नागरिक देवो भवः की साफ झलक दिखाई देती है।"

◆ 5. पीएम मोदी ने कहा, "जब आपने हमें 2014 में सेवा का अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की, हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया।

हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स संभव हो पाया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर भावपूर्ण विदाई दी गई

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दी भावभीनी विदाई

गांधीनगर, 20 सितंबर : विदाई दी।

गए। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भावपूर्ण मुख्य सचिव श्रीमती सुनयना तोमर,

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को गुजरात का अपना एक दिवसीय दौरा समाप्त कर दिल्ली के लिए रवाना हो

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी.आर. पाटिल, प्रोटोकॉल मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, राज्य के मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की अपर अहमदाबाद पुलिस आयुक्त श्री जी.एस. मलिक और चीफ प्रोटोकॉल अधिकारी श्री ज्वलंत त्रिवेदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री को भावभीनी विदाई दी।

सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन' विषय पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 सितंबर से विशाखापत्तनम में आरंभ होगा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 'विकसित भारतः सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन' विषय पर आयोजित दो दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

(जीएनएस)।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीईजी) का आयोजन कर रहे हैं। दो दिन का यह सम्मेलन 22-23 सितंबर, 2025

को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है 'विकसित भारतः सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन'।

सम्मेलन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह करेंगे। इस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश के आईटी एवं मानव संसाधन विकास मंत्री श्री एन. लोकेश भी उपस्थित रहेंगे।

आईसीजी ने 26,000 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ देश भर में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2025 का आयोजन किया

स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री के "स्वच्छता ही सेवा" (एसएचएस) आह्वान के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने 20 सितंबर 2025 को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2025 मनाया। एनसीसी कैडेटों, एनएसएस सदस्यों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों सहित 26,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने तटीय स्वच्छता को बहाल करने के लिए समुद्र तट सफाई अभियान में शामिल हुए और कूड़ा-कचरा तथा समुद्री मलबा हटाया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अमरेली जिले की सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सभा के 'सहकार से समृद्धि' परिसंवाद में सहभागी हुए

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 21 सितंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल रविवार को अमरेली में सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास परिषद के 'सहकार से समृद्धि' परिसंवाद में सहभागी हुए।

इस अवसर पर अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक, अमरेली जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लि. झ अमर डेयरी, अमरेली जिला सहकारी संघ, अमरेली जिला सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. आदि सहकारी संस्थाएँ

शामिल हुईं।

श्री पटेल ने जिले की सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सभा को 'सहकार से समृद्धि' को साकार को करने वाला अवसर बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात के दो सपूतों पूज्य महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभभाई पटेल की अगुवाई में गुजरात अग्रसर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन ने सहकारिता गतिविधि को गति देने का कार्य किया था। गांधीजी ने ग्राम स्वराज तथा सरदार पटेल ने किसानों को एकजुट कर दूध सहकारी मंडलियों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता की हमारी मूल भावना को बदलते समय के साथ सुसंगत रखकर नया कलेवर देने की दिशा दी है। उनके नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद पृथक सहकारिता मंत्रालय शुरू हुआ है।

Vibrant GUJARAT REGIONAL CONFERENCES

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

Gujarat Tourism

संस्कृति का श्रृंगार
आराधना का एकाकार

unesco
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

गुजरात में नवरात्रि केवल गरबा या रास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नौ दिवसीय उत्सव लोकसंगीत, पारंपरिक वेशभूषा और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का जीवंत संगम भी है।

उद्घाटक
श्री भूपेन्द्रभाई पटेल
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात

22 सितंबर, 2025 शाम 8:00 बजे से
गुजरात युनिवर्सिटी ग्राउंड, हेल्मेट चौराहा के पास, अहमदाबाद

सभी के लिए निःशुल्क प्रवेश

लोकेशन के लिए स्कैन करें

गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड
उद्योग भवन, ब्लॉक नंबर 16,
चौथी मंजिल, सेक्टर-11, गांधीनगर - 382 010
www.gujarattourism.com
टोल फ्री नंबर: 1800 203 1111

बुकिंग के लिए स्कैन करें

उद्घाटन समारोह
"आह्वान माँ आद्यशक्ति" की थीम पर पहली बार 1000 से अधिक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम

शेरी गरबा
• प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मुख्य मंच पर प्रस्तुति दी जायेगी (पारंपरिक वेशभूषा अनिवार्य)
• छोटे ग्रूप्स के लिए 9 विशेष गरबा ज़ोन

प्रमुख आकर्षण
• थीमेटिक एम्बियन्स • फूड स्टॉल • हस्तशिल्प बाज़ार • किड्स सिटी (बालनगरी) • सेल्फ़ी पॉइंट्स

सम्पादकीय

जारी है यूएस का भारत के प्रति एच1बी वीजा शुल्क रूपी दुराशय

इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सलाहकार मंडली जुबान से तो भारत और प्राधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए मीठी-मीठी बातें तो करती हैं किन्तु कार्रवाई इस तरह की करने में व्यस्त हैं जिससे देश के हर वर्ग को प्राभावित होना पड़ता है। शक्रवार को भी ट्रंप ने इसी दुराशय के वशीभूत होकर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत एच1बी वीजा शुल्क पर एक लाख अमेरिकी डालर बढ़ा दिया है। निति रूप से ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर प्रातिवूल प्राभाव पड़ना तय है। व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्प ने कहा कि एच1बी गैर प्रावासी वीजा कार्यव्रम देश की वर्तमान वीजा प्राणाली में सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली वीजा प्राणालियों में से एक है।

दरअसल जब कोई व्यक्ति इतना ज्यादा किसी के प्राति द्वेष रखता है तो कभी-कभी उसकी नकारात्मक कार्रवाई भी लक्षित व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र के हित में ही साबित हो जाती है। भारत तो बहुत ही प्रातिभा पलायन के कारण कई क्षेत्रों में पेशेवरों के टोटा होने से परेशान है। भारत में तमाम आईआईटी और एनआईटी होने के बावजूद विकासोन्मुख भारत को मेक इन इंडिया के लिए प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। पहले तो भारत में सुविधा न मिल पाने के कारण भारत से टेक्नालाजी संस्थानों से स्नातक की डिग्री लेकर डालर की लालच में युवक अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में चले जाते थे किन्तु आज देश में ऐसे महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए भारत में सुविधाओं की कमी नहीं है। निति रूप से भारतीय पेशेवरों को लक्ष्य बनाकर लागू की जाने वाली अमेरिकी वीजा नीति से अप्रात्यक्ष लाभ भारत को ही होगा क्योंकि हमारी प्रातिभा हमारे घर में ही रहेगी। भारत में आज वुशल कामगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। यदि अमेरिका से प्रौद्योगिकी और आईटी के पेशेवर भारत वापस आ जाएं तो न सिर्प भारत में स्टार्टअप्स की बाढ़ आ जाएगी और जरूरतमंद वंपनियों को मानव संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे बल्कि अमेरिका में जो भारतीय पेशेवर वहीं के लिए समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, उनकी हालत दिन प्रातिदिन प्रातिभा के अभाव में संकटग्रास्त हो जाएगा। भारतीय पेशेवरों और चीन के अमेरिका में अध्ययन करने वाले छात्रों की तुलना करें तो एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है कि चीनी छात्र पढ़ाई पूरी करके अपनी प्रातिभा और अनुमान का लाभ अपने देश को देने चीन चले जाते हैं किन्तु भारतीय संस्थानों में पढ़े लिखे छात्र अमेरिका को अपना ही देश मानकर जीजान से उसके विकास के लिए जुटे रहते हैं। फिर अमेरिका को वुछ दिनों या वर्षो बाद इस बात का एहसास होगा कि उनके एक राष्ट्रपति कितने नासमझ थे जिनकी वजह से भारतीय प्रातिभा से उनके देश की वंपनियां वंचित हो गईं। भारतीय इंजीनियरों, डाक्टरों और शिक्षकों ने अमेरिका को अपना देश मानकर वर्षो से जो तपस्या की है उन्हीं का परिणाम है कि आज अमेरिका हर क्षेत्र में शिखर पर है। अमेरिका को यह बात महसूस करनी चाहिए कि वह शीर्षस्थ शिखर पर पहुंच चुका है और प्रावृति का नियम यही है कि जो एक बार शीर्षस्थ हो जाता है उसका नीचे खिसकना अनिवार्य है। शीषरेन्मुखी है, उसे शीर्ष के शिखर पर पहुंचना ही है, इसलिए लगता यही है कि ट्रंप और उनके सलाहकारों ने पेशेवर प्रावासी भारतीयों के खिलाफ नीति निर्धारण करके अप्रात्यक्ष रूप से भारत को ही लाभ पहुंचाने का कार्य किया है।

श्री अमित शाह ने जोधपुर में 'श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय' के भवन और विधार्थियों के लिए छात्रावास का शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विशेष रूप से सक्षम लोगों को 'दिव्यांग' कहकर उन्हें देखने के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया

दिव्यांग शब्द देकर मोदी जी ने सभी दिव्यांगजनों में नए आत्मसम्मान, नई पहचान और आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न जगाने का काम किया

जब दिव्यांगों को दया की जगह दिव्यता का प्रतीक मानने की शुरूआत होती है, तब सच्चे अर्थों में दिव्यांगजनों के लिए काम होता है

श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय लोगों को दिव्यांगों को अपनाने और उन्हें मिली विशिष्ट शक्ति को पहचानकर आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहा है

मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों के कौशल को पहचानकर उन्हें उचित मंच देने का काम किया

समाज, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर अगर दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए काम करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है

मोदी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार के 1314 भवनों, 90 हवाईअड्डों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने का काम किया

आजादी से 2014 तक सिर्फ 7 लाख लोगों को केंद्र सरकार ने कृत्रिम अंग व यंत्र दिए थे, मोदी सरकार ने 10 वर्षों में 31 लाख से अधिक लोगों को कृत्रिम सहायता अंग दिए

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज राजस्थान के जोधपुर में 'श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय' के भवन और विधार्थियों के लिए छात्रावास का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सहित और केंद्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को दिव्यांगों के सेवा कार्यों से जोड़ता है, तो वह अनेक लोगों को प्रेरित भी करता है और लोगों को इस काम के साथ भी जोड़ता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने दिव्यांगो को भी कोई न कोई विशिष्ट शक्ति दी है और उस शक्ति को पहचानकर उनके जीवन को सरल बनाने के भाव को सुशीला जी के जीवन से हजारों लोगों ने ग्रहण किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि लगभग

15 करोड़ रुपए की लागत से तीन परियोजनाओं का आज यहां शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संस्था के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार यह तीनों परियोजनाओं का काम समय पर पूरा होगा जिससे सैकड़ों बच्चों के जीवन में नया उजियारा आएगा। उन्होंने कहा कि सुशीला जी ने 5 विद्यालयों, दो महाविद्यालयों, निःशुल्क छात्रावास, भोजन, ऑडियो बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन रीडर, कम्प्यूटर लैब और पुस्तकालय के माध्यम से दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं के जीवन में ज्ञान और दृष्टि का प्रकाश प्रसारित किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय 2022 में राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय बना। जब दिव्यांगों को दया की जगह दिव्यता का प्रतीक मानने की शुरूआत होती है तब सच्चे अर्थों में दिव्यांगजनों के लिए काम होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2015 में पहली बार विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। यह शब्द ही द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी के एक ही फैसले से पूरे भारत की जनता, सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार का दिव्यांगजनों को देखने का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सभी दिव्यांगों के अंदर दिव्यांग शब्द से नए आत्मसम्मान, नई पहचान, आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न जगाने का काम किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के सभी दिव्यांगजनों के अंदर मौजूद खेल कौशल को प्लेटफॉर्म दिया है। विश्व में पैरालंपिक खेलों की शुरूआत 1960 में हुई और तब से 2012 तक हुए सभी पैरालंपिक खेलों में भारत को सिर्फ 8 पदक मिले थे। पिछले तीन पैरालंपिक खेलों में भारत ने 52 पदक जीते और इससे हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। श्री शाह ने कहा कि समाज, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर अगर दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए काम करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक खेलों में 52 पदक जीतना इस बात को दशार्ता है कि हमारे दिव्यांगजन सब कुछ कर सकते हैं, बस जरूरत है उनका हाथ थामने, उनके अंदर की शक्ति को पहचान कर उन्हें उचित मंच प्रदान करने की।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के बजट को 2014 के 338 करोड़ से रुपए से बढ़ाकर आज 1313 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया है। सुगम्य भारत अभियान के तहत भारत सरकार के 1314 भवनों में 563 करोड़ रुपए खर्च कर उन्हें दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया है। इसके अलावा, 1748 अन्य इमारतों को भी सुगम्य बनाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि 35 अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों और 55 घरेलू हवाईअड्डों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने का काम भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले सिर्फ 7 लाख लोगों को भारत सरकार ने कृत्रिम अंग और यंत्र दिए थे, लेकिन मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में 18 हजार शिविर लगाकर 31 लाख लोगों को कृत्रिम सहायता अंग देने का काम किया गया है।

'दुर्गा आराधना पर्व : नवरात्रि'

माँ की महिमा, वात्सल्य एवं स्नेह तो शब्दों से परे है। माँ की सृजन शक्ति अतुलनीय है। माँ का त्याग, समर्पण और प्रेम अद्वितीय है। ऐसी ही जगतमाता, जगदंबा, भगवती हमारे कल्याण के लिए नवरात्रि में शक्ति की आराधना के उत्सव पर्व में गज पर सवार होकर पधार रही है। शिव सदैव शक्ति के साथ अपनी पूर्णता से सुशोभित होते है। वे अर्धनारीश्वर स्वरूप में स्त्री सम्मान को प्रदर्शित करते है। प्रत्येक ईश्वरीय सत्ता में हमें नारी के प्रति समभाव दिखाई देता है, फिर चाहे वह राधे-कृष्ण हो, सीता-राम हो, उमा-शंकर हो या लक्ष्मी-नारायण स्वरूप हो। उच्चारण में भी नारी को ही प्रथम स्थान दिया गया है।

माँ की करुणा तो सदा भक्तो के लिए मंगलकारी होती है। माँ भी सदैव सृष्टि के संचालन को सुचारु रूप से चलाने के लिए ईश्वर के साथ लीलाओं में सहयोगी होती है। सती का रूप धारण कर माँ भक्तों के लिए 51 शक्ति पीठों के रूप में आशीर्वाद प्रदान करने के लिए विराजमान हो गई और प्रत्येक भक्त के लिए माँ ने भिन्न-भिन्न स्थानो को चयनित किया। माँ तो सर्वत्र विद्यमान है। माँ का न तो आदि है न अंत। दयामयी, कृपालु माँ तो अंत में भैरव को भी क्षमा कर अपने दर्शन में सहज रूप में सम्मिलित करती है। इतनी उदारता तो केवल माँ के स्वभाव में भी परिलक्षित हो सकती है। माँ की ममता को भला कौन भक्त अनुभव नहीं कर सकता, यदि वह सच्चे मन से स्मरण करें तो माँ सदैव सहायक होती है। दानवों के अत्याचार से भक्तों एवं संतो को बचाने के लिए माँ सिंह पर सवार होकर आती है और सृष्टि को पाप के भय से मुक्त करती है।

माता का एक सरल स्वभाव होता है कि वह बालक की गलतियों को नहीं, बल्कि सदैव उसके अच्छे गुणों एवं कर्मों को याद रखती है, इसलिए यदि हम ईश्वर से भक्ति-भाव के साथ जुड़ जाए तो यह समबंधन ईश्वर भी समान रूप से निर्वहन करते है। यदि हम माता के आगमन की प्रतीक्षा करते है तो माँ भी हमारे पुकारने की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती है। जब बच्चा माँ के पास आकर बैठता है और अपने मनोभाव एवं दशा माँ को बताता है तब माँ ही तो होती है जो सुनने एवं समझने का प्रयास करती है। वह प्रत्येक स्थिति में बालक की उन्नति चाहती है। उसकी प्राथमिकता में सदैव बालक का हित निहित होता है। जगतमाता तो सर्वस्व कल्याणी एवं भक्त वत्सल स्वरूपा है। वे कैसे भक्तों की पुकार पर मनोवांछित एवं यथेष्ठ फल न प्रदान करें। श्रीराम कथा में स्वयं माता सीता ने माता पार्वती की स्तुति की थी और कहा था कि माँ आप तो शिव प्रिया एवं वरदान देने वाली हो। आप तो अपने भक्तों को चारों पुरुषार्थ सहजता से प्रदान कर देती है। जिस तरह बालक के हृदय में माँ का निवास होता है वह अपनी प्रत्येक इच्छा पूर्ति के लिए माँ से ही आस लगाता है, वैसे ही माँ के हृदय में भी सदैव बालक की चिंता विद्यमान होती है।

वर्तमान समय में हम

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

आइए, मनाए
GST बचत उत्सव

Next Generation GST REFORMS

देशवासी करेंगे ज़्यादा बचत, स्वदेशी को मिलेगी नई ताक़त!

आज से नेक्स्ट जनरेशन टैक्स रिफॉर्म की शुरुआत

दैनिक उपयोग की घरेलू वस्तुओं से लेकर वाहन तक, अब सब होगा सस्ता!

नई व्यवस्था, नए फायदे

- अब, ५% और १८% ऐसे सिर्फ दो टैक्स स्लैब
- दैनिक उपयोग की वस्तुएँ और सेवाएँ जैसे खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, साबुन, ब्रश, स्वास्थ्य बीमा आदि होंगे सस्ते
- १२% स्लैब में आने वाली ९९% वस्तुओं पर अब सिर्फ ५% **GST**
- घर, टीवी, फ्रिज, स्कूटर-बाइक, कार और होटल जैसी सेवाएँ होंगी और सस्ती

हर वर्ग को राहत

- ग़रीब, मध्यम वर्ग और नियो मध्यम वर्ग
- किसान, महिलाएं, व्यापारी और उद्यमी
- **MSMEs,** लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग
- भारत के हर परिवार की बचत बढ़ेगी

आगे बढ़ेगा देश

- सालाना ₹२.५ लाख करोड़ से अधिक की बचत
- **MSMEs** को दोगुना फ़ायदाः घटेगा टैक्स, बढ़ेगी बिक्री
- बढ़ेगा निवेश, व्यापार होगा अब और आसान
- "वन नेशन, वन टैक्स" - भारत की विकास यात्रा को मिलेगी नई रफ़्तार

॥ नागरिक देवो भवः ॥

अब "गर्व से कहो स्वदेशी मेरा स्वाभिमान है"

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी

एमआईबीएसआईआर ने बदली गुजरात के ग्रामीण विकास की तस्वीर, स्थानीय रोजगार और अवसरों में भारी वृद्धि

गांधीनगर, 21 सितंबर :गुजरात आज केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल हब के रूप में सामने आ रहा है। इस उपलब्धि के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दूरदर्शी 'ब्रेन-चाइल्ड कॉन्सेप्ट' मांडल-बेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेन्ट रीजन (MBSIR) भी बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसने न केवल गुजरात की ऑटो इन्डस्ट्री को नया आकार दिया है, बल्कि इस सेक्टर के लिए और भी कई नई संभावनाएँ सृजित की हैं। टइरक्फ़ में मारुति सुजुकी और होंडा जैसी विश्वप्रसिद्ध कंपनियों के स्थापित होने से स्थानीय व्यापार और रोजगार को नई गति मिली है और लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।

बेचराजी के प्रद्युमनसिंह झाला का वार्षिक टर्नओवर ₹3.50 करोड़, कभी करते थे ₹30 हजार की नौकरी

मांडल-बेचराजी के औद्योगिक विकास के कारण बेचराजी के रहने वाले 31 वर्षीय प्रद्युमनसिंह झाला एक अग्रणी व्यवसायी बन गए हैं और करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। बी.ई. मैकेनिकल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 30 हजार रुपये की सैलरी से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की थी। आज बेचराजी में उनके पास जेके टायर, ब्रिजस्टोन, योकोहामा और एक्साइड की डीलरशिप है और वे हर महीने एक लाख रुपये से अधिक का मुनाफा कमा रहे हैं।

प्रद्युमनसिंह झाला बताते हैं, 'मैं पिछले 4 वर्षों से टायर व्यवसाय से जुड़ा हूं। शुरूआत में हमारा वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपये था, जो आज लगभग साढ़े 3 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हमारी पास खुद की जमीन थी, लेकिन जब टइरक्फ़के कारण यहाँ सड़क और अन्य औद्योगिक सुविधाएं विकसित हुईं, तभी हम व्यवसाय शुरू कर पाए। टइरक्फ़ की वजह से गांव का भी अच्छा विकास हुआ है और लोगों को अलग-अलग व्यवसायों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।'

अहमदाबाद के माडंल तालुका के सीतापुर गांव के रहने वाले अमरसिंह ठाकोर, जो खेती और निर्माण व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्होंने बताया, 'सीतापुर और आसपास के गांवों के लोगों को यहां स्थापित हुई कंपनियों में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ये अवसर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के श्रमिकों को प्राप्त हुए हैं। एक समय था जब लोग नौकरी की तलाश में पलायन करते थे, लेकिन टइरक्फ़के कारण पलायन अब लगभग खत्म हो गया है। आज औद्योगिक क्षेत्रों की चहल-पहल के चलते छोटे-बड़े कारोबार का विस्तार हुआ है। यहाँ किराना, कपड़ा, डेयरी जैसे छोटे व्यवसायियों को भी लाभ मिला है।'

बेचराजी से 3 किलोमीटर दूर चांदणकी गांव में टी स्टॉल चलाने वाले सुरेशभाई बजाणिया ने बताया, 'टइरक्फ़बनने से पहले केवल गांव के लोग या फिर एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले लोग ही कभी-कभी चाय पीने मेरी दुकान में आते थे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में गुजराती चलचित्र पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 20 सितंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साफ तौर पर कहा कि कला सरकार आश्रित नहीं, बल्कि सरकार पुरस्कृत होती है, ऐसी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विकसित की गई परंपरा पर आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार गुजराती फिल्मों के कलाकारों को सम्मानित करते हुए टैलेंट को भी प्रोत्साहित कर रही है।

राज्य सरकार की ओर से आयोजित गुजराती चलचित्र पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियां और वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मुळुभाई बेरा, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, विधायक

श्री अमित ठाकर, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांग दाणी, उप महापौर श्री जतिनभाई पटेल और शहर अध्यक्ष श्री प्रेरक शाह की विशेष उपस्थिति में विभिन्न श्रेणियों में 43 अवॉर्ड्स प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गुजरात में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जो सर्वांगीण विकास हुआ है, उसके परिणामस्वरूप अन्य उद्योगों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री भी गुजरात के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की ओर आकर्षित हुई है और विकास का रोल मॉडल बना गुजरात फिल्म उद्योग का भी हब बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ गुजरात अब एंटरटेनमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए भी पसंदीदा गंतव्य बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसमें फिल्म और कला जगत के स्टार्टअप्स का भी अहम योगदान है।

उन्होंने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि गुजराती फिल्मों के बदलते कलेवर, मातृभाषा के प्रति लोगों के बढ़ते लगाव और उत्साह तथा सामाजिक विषयों पर केंद्रित फिल्मों के युग के परिणामस्वरूप गुजराती फिल्में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी देश और राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

पूरे देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में लोगों की व्यापक भागीदारी दर्ज की गई

अभियान के तहत 2.83 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें देश भर में 76 लाख से अधिक नागरिकों ने भाग लिया है

(जीएनएस)।

17 सितंबर 2025 को शुरू किए गए "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" अभियान में पूरे भारत में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखी जा रही है और लाखों महिलाएं, बच्चे और परिवार व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

20 सितंबर 2025 तक, इस अभियान के तहत 2.83 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर (जांच और विशेष शिविर) आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें देश भर में 76 लाख से अधिक नागरिकों ने भाग लिया है।

इस अभियान के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :

- उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जाँच: 37 लाख से ज्यादा नागरिकों की उच्च रक्तचाप और 35 लाख से ज्यादा लोगों की मधुमेह की जाँच की गई।
- कैंसर की जाँच: 9 लाख से ज्यादा महिलाओं की स्तन कैंसर और 4.7 लाख से ज्यादा महिलाओं की गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जाँच की गई। मुख कैंसर की जाँच में 16 लाख से ज्यादा लोगों की जाँच की गई।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य: 18 लाख से ज्यादा प्रसवपूर्व जाँचें की गईं, जबकि 51 लाख से ज्यादा बच्चों को जीवन रक्षक टीके लगाए गए।
- एनीमिया और पोषण: 15 लाख से ज्यादा लोगों की एनीमिया की जाँच की गई। पोषण परामर्श सत्र लाखों परिवारों तक पहुँचा।

एनएचआरसी, भारत विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ग्लोबल साउथ के एनएचआरआई के वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करेगा

6 दिवसीय कार्यक्रम 22 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में शुरू होगा

कार्यक्रम का उद्देश्य मानव अधिकारों के विभिन्न आयामों, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना और विभिन्न एनएचआरआई के प्रतिभागियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एनएचआरसी, भारत के अनुभव को साझा करना है

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत, विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से, 22 से 27 सितंबर, 2025 तक नई दिल्ली में ग्लोबल साउथ की राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के वरिष्ठ-स्तरीय पदाधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर छह दिवसीय भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्लोबल साउथ की राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। यह वैश्विक मानव अधिकार संवाद, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और अधिकार-आधारित शासन की सामूहिक उन्नति के प्रति एनएचआरसी भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह कार्यक्रम भाग लेने वाले देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) की आवश्यकताओं और आयोग द्वारा आयोजित तीन पूर्व आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के दौरान प्राप्त फीडबैक के अनुसार बनाया गया है। मॉरीशस, जॉर्डन, जॉर्जिया, फिलीपींस, कतर, फिजी, उज्बेकिस्तान, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, मोरक्को और पैराग्वे के 12 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है।

एनएचआरसी भारत के तीन दशकों से भी अधिक के अनुभव का लाभ लेने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्लोबल साउथ में वकालत, प्रवर्तन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए एनएचआरआई के बीच गहरी समझ, पारस्परिक शिक्षा और सार्थक सहयोग को बढ़ावा देना है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करने में विशेषज्ञता और क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेषज्ञ होंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन द्वारा किया जाएगा।

इसके अपेक्षित परिणामों में मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय आयामों की बेहतर समझ विकसित करना; एनएचआरसी की गहन समझ, मानव अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में भारत के कार्य और इसकी सर्वोत्तम व्यवस्थाएं जिनको अन्य एनएचआरआई अपना सकती है;

भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) और स्वायत्त निकाय विशेष अभियान 5.0 के लिए तैयार

(जीएनएस)।

कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवेश में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के अनुरूप, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 5.0 (एससीडीपीएम 5.0) के प्रारंभिक चरण की सफलतापूर्वक शुरूआत कर दी है। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखने और लंबित मामलों में कमी लाने के लिए, मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों ने अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाये हैं।

15 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक की तैयारी गतिविधियों के एक भाग के रूप में, मंत्रालय अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों के सहयोग से, प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए पुरानी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की गहन समीक्षा कर रहा है। अनुपयोगी वस्तुओं, स्क्रैप सामग्री और ई-स्क्रैप की पहचान और निपटान द्वारा इन प्रयासों को पूरक बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कार्यालय के बहुमूल्य स्थान को मुक्त करना और बेहतर कार्यस्थल व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

एमएचआई के अंतर्गत विभिन्न सीपीएसई और स्वायत्त निकायों ने विशेष अभियान 5.0 के तहत खाली किए जाने वाले स्थानों और कबाड़ के निपटान हेतु स्थानों की पहचान की है

कार्यालय परिसरों और औद्योगिक इकाइयों में स्वच्छता अभियानों की एक श्रृंखला की तैयारी भी चल रही है। ये अभियान न केवल भौतिक स्वच्छता पर बल्कि सुरक्षित, व्यवस्थित और पेशेवर कार्य वातावरण के निर्माण पर भी जोर देंगे। मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जवाबदेही, स्वच्छता और व्यवस्था की संस्कृति विकसित करने में इस अभियान की भूमिका को मान्यता देता है।

20 सितंबर 2025 तक तैयारी चरण के दौरान सीपीएसई और स्वायत्त निकायों द्वारा पहचाने गए प्रमुख लक्ष्यों में शामिल हैं:

कार्यालय परिसरों और औद्योगिक इकाइयों में गहन स्वच्छता अभियान के लिए 103 स्थल चिन्हित किए गए हैं।

- अव्यवस्थित और पुरानी सामग्रियों के निपटान के माध्यम से बेहतर उपयोग के लिए 1,58,405 वर्ग फुट स्थल की पहचान की गई है।
- रिकॉर्ड प्रतिधारण नीतियों के अनुसार समीक्षा और छंटाई के लिए 4,905 भौतिक फाइलों का चयन किया गया है।

श्री पीयूष गोयल ने नामकरण की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) कोड के मानचित्रण पर मार्गदर्शन पुस्तक का अनावरण किया

यह मार्गदर्शन पुस्तक उत्पादों को उनके संबंधित मंत्रालयों और विभागों से जोड़कर तीक्ष्ण नीतिगत हस्तक्षेपों और प्रभावी व्यापार वार्ताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके विकसित भारत@2047 की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है: श्री गोयल

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में "मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने का समारोह और अगली पीढ़ी के सुधार 2.0 पर चर्चा" कार्यक्रम के दौरान उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा तैयार नामकरण की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) कोड के मानचित्रण पर मार्गदर्शन पुस्तक का विमोचन किया। यह मार्गदर्शन पुस्तक भारत सरकार के 31 मंत्रालयों और विभागों को 12,167 एचएसएन कोड आवंटित करती है। इसका उद्देश्य विनिर्माण विकास, निवेश प्रोत्साहन और व्यापार सुगमता के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण को अपनाने को बढ़ावा देना है। यह एक लचीले और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण तंत्र के निर्माण की नींव का काम करेगी।

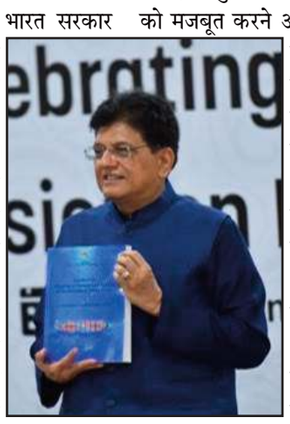

इसके महत्व पर जोर देते हुए, श्री गोयल ने उल्लेख किया कि यह मार्गदर्शन पुस्तक घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके अतिरिक्त, यह राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं और डोमेन की मजबूती के अनुरूप, अधिक प्रभावी व्यापार समझौता वार्ताओं को भी बढ़ावा देगा। विशिष्ट एचएसएन कोड के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग की पहचान की सुविधा के साथ, यह पहल नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगी और व्यापार सुगमता को और बढ़ाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यह मार्गदर्शन पुस्तक 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में एक अभिन्न भूमिका निभाएगी, जिसमें शासन उद्योग की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होगा।

इस मार्गदर्शन पुस्तक के विकास का मूल, व्यापार वार्ताओं, आयात प्रतिस्थापन प्रयासों और एचएसएन कोडों की निश्चित मैपिंग के अभाव के कारण उद्योग जगत की चिंताओं के निवारण के दौरान उत्पन्न होने वाली लगातार चुनौतियों के अवलोकन में निहित है।

भविष्य के बीज: स्वच्छ पौध कार्यक्रम ने पकड़ी रफ्तार

रोग-मुक्त पौध सामग्री से भारतीय बागवानी का कायाकल्प

(जीएनएस)।

स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत, देश भर में 9 स्वच्छ पौध केंद्र बनाए जाएँगे, ताकि रोगमुक्त और उत्पादक पौध सामग्री उपलब्ध हो सके।

- महाराष्ट्र में 300 करोड़ रुपए की लागत से 3 केंद्र स्थापित किए जाएँगे।
- बागवानी में क्रांति लाने के लिए संसाधनों और ताजा जानकारियों के एक मुख्य केंद्र के रूप में सीपीपी वेबसाइट की शुरूआत की गई।
- आधुनिक नर्सरियों द्वारा किसानों को प्रतिवर्ष 8 करोड़ रोगमुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएँगे।
- जोखिम विश्लेषण, नर्सरी जाँच और प्रयोगशाला सुधार जैसी जमीनी गतिविधियाँ जारी हैं, साथ ही प्रमाणन, प्रशिक्षण और फसल प्रोटोकॉल का विस्तार करने की भी योजना है।

प्रस्तावना : पौधों के स्वास्थ्य के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जैविक और अजैविक खतरे भी बढ़ रहे हैं। इन चुनौतियों से सीधे तौर पर कृषि में घाटा देखा जा रहा है, जिससे किसानों की आय और समग्र उत्पादकता में भी कमी आ रही है। हांलाकि भारत ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने में खासा निवेश किया है, फिर भी प्रणालीगत रोगजनक (मुख्यतः विषाणु) एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, जिससे उपज में भारी नुकसान हो रहा है। ये रोगजनक फसल की मात्रा, गुणवत्ता और जीवन काल को कम कर देते हैं। जब तक लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक किसानों के लिए खेत में रोगों का प्रबंधन करना अक्सर नाममकिन हो जाता है। इसलिए, रोगमुक्त रोपण सामग्री से शुरूआत करना, इन चुनौतियों से निपटने की सबसे प्रभावी रणनीति मानी गई है।

इस समस्या से निपटने के लिए, बीज की गुणवत्ता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने और स्वच्छ पौध कार्यक्रमों को लागू करने जैसे निवारक उपायों को बड़े स्तर पर मान्यता दी गई है। ऐसे उपाय न केवल पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, बल्कि प्रतिकूल नुकसान से मुक्त होने का अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करते हैं। इसी लिहाज से, 9 अगस्त 2024 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) को मंजूरी दे दी।

अवलोकनः स्वच्छ पौध सामग्री की अनिवार्यता

स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) किसानों को उच्च-गुणवत्ता वाली, विषाणु-मुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के सहयोग से एक कार्यान्वयन और क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो तकनीकी प्रगति की निगरानी करता है और क्षमता निर्माण में भी मदद करता है। इस पहल में 1,765.67 करोड़ रुपए का अहम निवेश शामिल है, जिसमें दिसंबर 2023 में एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत 98 मिलियन डॉलर का ऋण भी शामिल है।

सीपीपी क्या है?

भारत का स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी), जिसकी कल्पना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग के साथ की है, एक नई पहल है, जिसका मकसद प्रमुख फल फसलों की स्वस्थ, रोगमुक्त पौध सामग्री सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम का मकसद किसानों की उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाना है, जिससे अंततः भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।

यह पहल निम्नलिखित नियोजित विकासों के साथ आकार लेने लगी है:

- रोगमुक्त, उत्पादक पौध सामग्री सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 9 स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इनमें से 3 केंद्र महाराष्ट्र में 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएँगे—पुणे (अंगूर), नागपुर (संतरा) और सोलापुर (अनार)।
- आधुनिक नर्सरियों को विकसित किया जाएगा, जिनमें बड़ी नर्सरियों के लिए 3 करोड़ रुपए और मध्यम नर्सरियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये नर्सरियाँ किसानों को हर साल 8 करोड़ रोगमुक्त पौधे उपलब्ध कराएँगी।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए इजराइल और नीदरलैंड जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जाएगा।
- सीपीपी के तहत मूल पौध प्रजातियों पर शोध के लिए पुणे में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई और प्रगति

परियोजना विजयक (बीआरओ) ने करगिल में 1,200 करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाओं के साथ अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया

(जीएनएस)।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की विशेष परियोजना विजयक ने 21 सितंबर, 2025 को लद्दाख के करगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। इसने 16वें वर्ष में प्रवेश करते हुए 1,200 करोड़ रुपये से अधिक लागत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार किया। यह अवसर विश्व के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सेवा, धैर्य और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की उल्लेखनीय यात्रा को उजागर करता है। पिछले 15 वर्षों में परियोजना विजयक ने लद्दाख में 1,400 किलोमीटर से अधिक सड़कों और 80 से ज्यादा प्रमुख पुलों का निर्माण व रखरखाव किया है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में अप्रैल 2025 में सर्दियों के बंद होने के बाद केवल 31 दिनों के भीतर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला दर्रे को फिर से खोलना भी शामिल है, जिसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में संपर्क सुविधा बढ़ाने में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर माना जाता है।

2010 में आरंभ की गई परियोजना विजयक को सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ लद्दाख की दूरस्थ घाटियों और अग्रिम क्षेत्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस परियोजना के योगदान से न केवल सेना की परिचालन तैयारियों को मजबूती मिली है, बल्कि लद्दाखवासियों के लिए संपर्क, सुविधाओं और आजीविका के नए अवसर भी विकसित हुए हैं।

15वें स्थापना दिवस समारोह ने परंपरा और गौरव दोनों का भव्य संगम प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर आयोजित स्मृति कार्यक्रमों में सैनिक सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंदिर एवं गुरुद्वारा में प्रार्थनाएं और शहीद नायकों की स्मृति में विजयक स्मारक का उद्घाटन करना शामिल थे। द्रास युद्ध स्मारक तक निकाली गई बाइक रैली, लद्दाखी संस्कृति पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिताओं और पागल जिमखाना व बाराखाना जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों ने सैनिकों, उनके परिवारों तथा स्थानीय नागरिकों को एकता एवं उत्साह की भावना से जोड़ दिया।

परियोजना विजयक ने अपने आकस्मिक वेतनभोगी श्रमिकों के कल्याण पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया है, जिन्हें इसके संचालन की वास्तविक रीढ़ माना जाता है। उनकी सुरक्षा और जीवन-स्तर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पृथक आवासीय आश्रय, बेहतर स्वच्छता सुविधा, उन्नत सुरक्षात्मक उपकरण, सर्दियों के कपड़े और नियमित स्वास्थ्य शिविर जैसी अनेक कल्याणकारी पहल सफलतापूर्वक लागू की गई हैं।

भविष्य की दृष्टि से 1,200 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना में प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, नई सुरंगों एवं पुलों का निर्माण, साथ ही भू-वस्त्र, उन्नत सतह, ढलान स्थिरीकरण, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण पद्धतियों जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का समावेश किया गया है। ये प्रयास लद्दाख की ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में लचीलापन, स्थायित्व व निर्बाध कनेक्टिविटी को और अधिक बेहतर बनाएंगे।

परियोजना विजयक अपने 16वें वर्ष में प्रवेश करते हुए सेवा और गौरव का प्रतीक बनकर खड़ी है। यह न केवल सशस्त्र बलों और स्थानीय आबादी के लिए जीवनरेखा का कार्य कर रही है, बल्कि देश के सबसे दुर्गम

'बिहार चुनाव में टिकट नहीं चाहिए, ना ही सांसद बनना', रोहिणी को क्यों कहना पड़ा ऐसा, तेजस्वी करवा रहे बदनाम?

(जीएनएस)।

बिहार में लालू परिवार में कथित कलह की खबरों के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। परिवार और आरजेडी से नाराजगी को लेकर किए जा रहे दावों को रोहिणी आचार्य ने निराधार बताया है। इसके साथ ही जमकर गुस्सा निकाला है।

पिता लालू यादव को अपनी किडनी दान करके उनकी जान बचाने के बाद खूब चर्चा में रहीं रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक बयान जारी किया। जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाया है कि ऐसे अफवाहें फैला कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन रोहिणी को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है क्या इसके पीछे उनके भाई तेजस्वी यादव हैं?